यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दो राज्यों के साथ शीर्ष पर पहुंचा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। देश में कारोबार और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की रेस में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने त्रिपुरा और ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है।

यह उपलब्धि केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक सुधार, नियमों में ढील और कंप्लायंस कम करने की सुनियोजित रणनीति रही है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे खराब रही है, जो देश में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की जानकारी दी।

नंबर वन रैंक हासिल करने के बाद यूपी सरकार अब कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डिरेगुलेशन फेज-2 को तेजी से लागू करने की तैयारी में जुट गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से 28 जनवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार, पहले चरण में 23 प्राथमिकता वाले सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इन्हीं सुधारों से प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब फोकस दूसरे चरण पर है, जिसमें 30 नए सुधार प्रस्तावों पर काम शुरू किया गया है। इन सुधारों के लागू होते ही यूपी में उद्योग, व्यापार, लघु व मध्यम उद्योग स्थापित करना पहले से आसान और सुलभ हो जाएगा।

राज्य और उनकी रैंकिंग

त्रिपुरा, ओडिशा के साथ यूपी को संयुक्त स्थान

पश्चिम बंगाल सबसे फिसड्डी

कौन से राज्य आगे और कौन पीछे

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर त्रिपुरा, ओडिशा और यूपी हैं। हरियाणा व मध्य प्रदेश दूसरे, मेघालय व राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे।
- आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, केरल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं।
- गति पकड़ने में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली और झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल सबसे नीचे 20वें स्थान पर है, जो उसकी कमजोर प्रशासनिक और नीतिगत स्थिति को दर्शाता है।

अब बड़े सेक्टरों में होगा सुधार

फेज-2 में शामिल क्षेत्र निवेश और कारोबार से जुड़े हैं। इनमें भूमि आवंटन, भवन निर्माण अनुमति, ऊर्जा, श्रम कानून, पर्यावरण स्वीकृति, पर्यटन और शिक्षा जैसे सेक्टर हैं। इन क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल करने, अनावश्यक अनुमतियों को खत्म करने और समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इन सुधारों के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार करने को कहा है, जबकि दो महीने के भीतर सभी सुधारों को लागू करने की समय सीमा तय की गई है।

> ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को देश में नंबर वन स्थान मिला है। यह उपलब्धि निवेशकों और उद्योग जगत के लिए साफ संदेश है कि सरकार कारोबार को लेकर गंभीर है। फेज-2 के सुधार के लिए काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को इसकी बैठक होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। जल्दी ही फिर बैठक कर सुधारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। **-प्रथमेश कुमार,** उपाध्यक्ष, एलडीए

सचिव आवास के नहोने से नहीं हो पाई बैठक

आवास विभाग में सुधारों को अमली जामा पहनाने के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 30 जनवरी को आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय में प्रस्तावित थी। हालांकि, सचिव आवास के अचानक बाहर चले जाने के कारण यह बैठक अंतिम समय पर रद्द कर दी गई। अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई तिथि तय कर बैठक बुलाई जाएगी, ताकि फेज-2 के सुधारों को गति दी जा सके।